



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50

संख्या: 315

प्रभात

कोटा, शुक्रवार 29 अगस्त, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जो सरकार नहीं कर पाई : एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 रद्द की

हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि एस.आई. भर्ती परीक्षा 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार ही पुनः आयोजित की जाए

- यादवेंद्र शर्मा -

जयपुर, 28 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यापक पेपर लीक और नकलबाजी के आरोपों को सही मानते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.) द्वारा एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर, महाधिवक्ता की राय के अनुसार 2021 की विज्ञप्ति में संशोधन कर पुनः आयोजित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई 2025 में जारी नई विज्ञप्ति में भी संशोधन कर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 2021 की भर्तियों को भरने का प्रावधान कर सकती है।

हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षण व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा

■ हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुनः आयोजित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को आयु सम्बन्धी योग्यता में रियायत दी जाए, साथ ही सभी योग्य अभ्यर्थियों को 2021 में मिल रहे आरक्षणों व अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए।

■ अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा को छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे।

■ न्यायाधीश समीर जैन ने अपने आदेश में तत्कालीन आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष संजय श्रौतिया समेत अन्य सदस्य, जिनमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन अफसरों ने व्यापक पेपर लीक को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई और आर.पी.एस.सी. की विश्वसनीयता को छलनी किया।

है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की सरकारी सेवा का छोड़ा था और फिर एस.आई. भर्ती परीक्षा में चयनित हुए

2025 तक योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश से वो कर दिखाया है जो पिछले डेढ़ वर्ष से राज्य सरकार करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि, जैसा कि विदित है कि इस मामले में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वी.के. सिंह, की देखरेख में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट दायर करी थी कि एस.आई. भर्ती-2021 में अपराधिक गिरोह शामिल थे, जिन्होंने आर.पी.एस.सी. के अध्यक्ष सहित छह सदस्यों के साथ मिलकर व्यापक पेपर लीक के षड्यंत्र को अंजाम दिया था और फिर चयनित अभ्यर्थियों से 'इंटरव्यू' में घूस के लिए अच्छे अंक देने का भी षड्यंत्र रचा था।

बताया जा रहा है कि इस मामले की शुरूआती जांच के दौरान स्वयं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिनेश पटनायक कैनडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त

नयी दिल्ली, 28 अगस्त। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के. पटनायक को कैनडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उनके शीघ्र ही पद भार ग्रहण करने की संभावना है।

पटनायक भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और वह स्पेन में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

उल्लेखनीय है कि कैनडा में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री

■ दो वर्ष पहले टूटो के शासनकाल में दोनों देशों में भारी तनाव के कारण कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे।

नरेन्द्र मोदी और कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच गत जून में जी-7 की आउटरीच बैठक के दौरान हुई मुलाकात में संबंधों को सुधारने पर बनी सहमति के बाद की गयी है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दिल्ली और ओटावा में उच्चायुक्तों की बहाली का निर्णय लिया था।

खालिस्तानी संगठन से जुड़े हरदीप सिंह निज्जर की दो वर्ष पहले हुई हत्या को लेकर जस्टिन टूडो सरकार ने इसमें भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। भारत ने इससे साफ इंकार किया था (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मैंने कभी नहीं कहा मैं 75 साल में रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को हो जाना चाहिए’

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की आयु में रिटायर होने के विवाद पर यह टिप्पणी की

- संघ प्रमुख भागवत के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में देखा जा रहा है।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को और मोहन भागवत 11 सितम्बर को 75 साल के हो रहे हैं।
- संघ प्रमुख ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सम्बंध में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी कहा कि भाजपा व आरएसएस के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं है। हमें एक-दूसरे पर विश्वास है।

जोता है, हम चाहें या न चाहें। अगर मैं 80 साल का हूं और संघ कहता है कि जाओ और शाखा चलाओ, तो मुझे करना ही होगा। संघ जो भी कहता है, हम करते हैं। यह किसी की सेवानिवृत्ति के लिए नहीं है। हम सेवानिवृत्त होने या काम करने के लिए तैयार हैं। जब तक संघ चाहता है।

उन्होंने कहा कि मैं शाखा चलाने में माहिर हूं, भाजपा सरकार चलाने में माहिर है, हम एक-दूसरे को सिर्फ

सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम फैसला नहीं करते, अगर हमें फैसला करना होता तो क्या इसमें इतना समय लगता।

भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद के सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास है...क्या भाजपा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘प्र.मंत्री मोदी की सतही विदेश नीति का देश को नुकसान ही हुआ’

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि, सरकार की मुस्कान, गले मिलने और “सेल्फी” लेने पर आधारित विदेश नीति, देश के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकी

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश की रक्षा करने में विफल रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जी.टी.आर.आई.) की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग एक प्रतिशत जीडीपी पर असर पड़ सकता है और इसका फायदा चीन को मिलेगा।

बुधवार से अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यापार समझौता न कर पाने और देश की रक्षा न कर पाने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चेतावनी दी कि टैरिफ की पहली मार में कम से कम 10 सेक्टरों को 2.17 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के दिखावटी कार्यक्रम, मुस्कान, गले लगाना और सेल्फी, ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। खड़गे ने कहा, “आपके प्यारे दोस्त

■ खड़गे ने इसी संदर्भ में यह भी कहा, कि “ट्रेड डील” (व्यापारिक समझौता) नहीं होने से 10 सेक्टरों में ही 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

■ भारत के “टैक्सटाइल उद्योग” में ही 5,00,000 नौकरियां खत्म हो जायेंगी। जैम्स व ज्वेलरी क्षेत्र में 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियां कम हो जायेंगी, हीरे की कटिंग व पॉलिशिंग उद्योग में भी एक लाख वर्कर बेरोजगार हो जायेंगे।

“अबकी बार, ट्रंप सरकार” ने आज से भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। हमारे किसान, खासकर कपास के किसान, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी “निजी कीमत” चुकाने को तैयार हैं, लेकिन आपने उनके नुकसान को कम करने और आजीविका बचाने के लिए कुछ नहीं किया।”

उन्होंने कहा कि कई निर्यात-आधारित अहम सेक्टर, खासकर एमएसएमई, में बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान होगा।

खड़गे ने कहा कि “भारतीय वस्त्र निर्यात क्षेत्र में लगभग 5 लाख नौकरियों का नुकसान हो सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है।”

उन्होंने बताया कि अगर शुल्क जारी रहा तो रत्न और आभूषण सेक्टर में भी 1,50,000 से 2,00,000 नौकरियों पर खतरा है। उन्होंने कहा, सौलद्र क्षेत्र में हीरे काटने और पॉलिश करने वाले करीब 1,00,000 मजदूरों की नौकरियां अप्रैल से ही जा चुकी हैं, जब अमेरिका ने 10 प्रतिशत बेस टैरिफ लगाया था।

जयपुर महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर

नई दिल्ली, 28 अगस्त। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक (एनएआरआई) 2025 के अनुसार, कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, इटानगर और मुंबई महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहरों के रूप में

■ राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट व महिला सुरक्षा सूचकांक 2025, के अनुसार जयपुर के साथ दिल्ली, पटना व कोलकाता महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित शहर हैं, वहीं, मुम्बई, कोहिमा, इटानगर आइजोल और भुवनेश्वर सर्वाधिक सुरक्षित माने गए हैं।

उभरे हैं, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्थान पर हैं। गुरुवार को जारी राष्ट्रव्यापी सूचकांक में, 31 शहरों की 12,770 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘वैश्विक नेताओं से निजी रिश्ते बनाने की मोदी की नीति के कारण भारत - अमेरिका सम्बंधों में संकट आया है’

एक पूर्व राजनयिक ने इसके साथ यह भी कहा कि मोदी को लगता था अमेरिका ही भारत की ग्रोथ का आधार है, मात्र अमेरिका पर निर्भरता का खामियाजा भुगत रहा है भारत

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा मोदी सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनाए गए कठोर रवैये से उन्हाहित होकर, वाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवैरो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष “मोदी की जंग” है।

मोदी सरकार को अमेरिकी फरमानों के आगे झुकने की स्पष्ट कोशिश करते हुए नवैरो दिल्ली पर दबाव बना रहे हैं। दिल्ली पर पहले से ही कई मोर्चे से दबाव पड़ रहा है। एच वन-बी वीजा कार्यक्रम को लेकर धमकियों से लेकर पाकिस्तान के साथ

■ अमेरिका क्यों हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ा है इस पर एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा तो बहाना मात्र है असली कारण अर्थव्यवस्था है। अमेरिका भारत के कृषि बाजार में घुसना चाहता है, और भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि यह देश के किसानों के लिए घातक होगा।

■ वाइट हाउस के ट्रेंज़री सैक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने भी इस बात की पुष्टि यह कहकर कर दी, कि विवाद सिर्फ “रूसी तेल” के कारण नहीं है। वॉशिंगटन की टैरिफ रण का निशाना तो भारत की “ट्रेड” सम्बंधी बाधाएं हैं।

संघर्ष विराम लागू करने के बार-बार किए जा रहे दावों तक।

अनुभवी विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत विदेश नीति शैली और विश्व

नेताओं से हरेक से एक निजी संबंध बनाने की उनकी इच्छा ने भारत-अमेरिका संबंधों में मौजूदा संकट को जन्म दिया है। एक पूर्व राजनयिक ने बताया कि मोदी और भाजपा इस

विश्वास में थे कि अमेरिका भारत की प्रगति की कुंजी है, और इसलिए वॉशिंगटन के साथ रिश्तों पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन जब सारे उम्मीदें एक पर ही टिका दी जाए, तो खतरा बढ़ जाता है।

ब्लूमबर्ग को बुधवार को दिए इंटरव्यू में नवैरो ने कहा, “भारत जो कर रहा है, उससे अमेरिका में हर कोई हार रहा है। उपभोक्ता, व्यवसाय, सब को नुकसान हो रहा है। नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आमदनी और मजदूरी पर असर पड़ रहा है। और फिर टैक्स देने वालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मोदी की जंग के लिए फंड देना पड़ रहा है।”जब उनसे पूछा गया कि क्या वे “पुतिन की जंग” कह रहे हैं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी जापान और चीन यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान और चीन के पांच दिवसीय दौरें रवाना हो गए। पीएम मोदी के दौरे का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। अमेरिकी टैरिफ

■ प्र. मंत्री मोदी पहले जापान जाएंगे, जहां वे दो दिन रहेंगे, इसके बाद वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे।

विवाद के बीच हो रही पीएम मोदी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही है। पीएम मोदी जापान के बाद चीन जाएंगे। जहां वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुकुमार साह -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 28 अगस्त। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ झटके के प्रति भारत ने झुकने की बजाय खुला विरोध कर सीधे मुकाबला करने का रास्ता चुना है। न तो किसी झूट के लिए याचिका दायर की जाएगी, न ही वॉशिंगटन के रुख में बदलाव का धैर्यपूर्वक इंतजार किया जाएगा। इसके बजाय, नई दिल्ली ने तीन-स्तरीय प्रतिकार रणनीति अपनाई है - अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए निर्यात बाजारों में विविधता लाना, कर सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना, और अगली पीढ़ी के नीतिगत परिवर्तनों में तेजी लाना।

■ भारत के नीतिकारों का मानना है, “डॉमैस्टिक कंज़प्शन” (देश की घरेलू डिमान्ड) का आज भी योगदान, जी.डी.पी. के आंकड़े में 61 प्रतिशत है, और कुछ और टैक्स आदि की रियायतें देकर भारत की “घरेलू डिमान्ड”, को और अधिक बढ़ाने की काफी गुंजाइश (स्कोप) है।

■ इसी दिशा में बढ़ते हुए, हाल ही में जी.एस.टी. का सरलीकरण करने की घोषणा की गई है, तथा दो ही “स्लैब” (वर्ग), 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत रह जायेंगे।

■ भारत का यह इतिहास रहा है कि जब भी विदेशी दबाव पड़ा है, भारत दबाव के आगे झुका नहीं। पं. नेहरू पर भारी दबाव था शीत युद्ध के जमाने में, अमेरिका का खेमा या रूस का खेमा जॉइन करने का, पर, उन्होंने “नॉन एलाइन्ड” (निर्मुक्त) रहने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी भी, 1971 के संकट के समय अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आईं तथा 1998 में एन.डी.ए. की सरकार ने “न्यूतिलियर टेस्ट” करने का फैसला किया, पाश्चात्य देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद।

यह रुख भारत की उस ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वह महाशक्तियों के दबाव का प्रतिकार करता आया है। नेहरू द्वारा शीत युद्ध के गुटों में शामिल होने से इनकार करने से लेकर इंदिरा गांधी द्वारा 1971 संकट के दौरान विरोध जताने और 1998 में पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु परीक्षणों को आगे बढ़ाने तक, यह प्रवृत्ति जानी पहचानी रही है। हर बार, भारत ने बाहरी दबाव को आत्मनिर्भरता जताने और दीर्घकालिक रणनीति को फिर से गढ़ने का अवसर बनाया है।

इसी भावना के तहत, मोदी सरकार इस टैरिफ वृद्धि को कोई गंभीर झटका नहीं बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में ले

रही है। अमेरिकी व्यापार आदेशों को बाध्यकारी न मानकर भारत यह संकेत दे रहा है कि वह अल्पकालिक कठिनाइयों को सहने को तैयार है, ताकि एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था बनाई जा सके - जो घरेलू मांग पर आधारित हो और जिसकी वैश्विक साझेदारियों में विविधता हो।

बुधवार से प्रभावी हुए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर अमेरिका को होने वाले भारत के 45 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा, जिसमें केवल दवाएं, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया गया है। वस्त्र, रत्न, झींगा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए यह वृद्धि कमजोर होती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बाढ़

सुकमा, 28 अगस्त । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार बारिश से उफान पर आई शबरी नदी और नालों के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गौदम नाला के पास 48 घंटे से फंसी बस में सवार यात्रियों को जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की

■ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 48 घंटे से फंसी बस के यात्रियों को बचाया गया। अब तक 2000 नागरिकों का पुनर्वास किया जा चुका है।

टीमों ने नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी 6 की गई।

जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। अब तक जिले के विभिन्न प्रभावित इलाकों में 22 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहाँ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

केवल आत्मज्ञान ही हृदयात्मा को सच्चा आनंद प्रदान करता है। –रामतीर्थ

चुनाव के हेतु मतदाता सूची चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326, 327 व 328 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बनाई जाती है



डॉ. अमृता कटारा

जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान की रैतीली धरती को हरी चादर ओढ़ाने का संकल्प लिए हरियालो राजस्थान अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यह सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं, बल्कि हरियाली के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाने के ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने के बाद अब लक्ष्य रखा है कि आने वाले वर्षों में पौधारोपण को और अधिक संगठित और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। इसके तहत पौधों की जियो-टैगिंग, नमी संरक्षण के लिए गड्डों में जल संचरना और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपनाई जा रही है। स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर तक

पौधारोपण को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति में 4.15 करोड़ पौधों का पौधारोपण कर प्रथम स्थान हासिल किया गया है। राज्य में शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों से जोड़ने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शिक्षा विभाग के मंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। यह पहल शिक्षा और पर्यावरण को साथ लाकर भविष्य की पीढ़ी को संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में मील का पथर साबित हुई।

राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ आमजन की भागीदारी को अभियान का सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने अब अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके लिए पौधारोपण को संगठित, तकनीकी और दीर्घकालिक स्वरूप देने पर जोर है। विद्यालयों के साथ

महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, युवा संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएँ और उद्योग जगत भी इस पहल से जुड़ रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में वृक्ष ही जीवनेरेखा हैं। इनसे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकेगा बल्कि भूमिगत जलस्तर भी सुधरेगा। साथ ही यह जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण में भी अहम योगदान देंगे। हरियालो राजस्थान अभियान से प्रदेश को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। पौधों से होने वाले औषधीय, औद्योगिक और फल-फूल उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी होगा और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेंगे।

हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हुआ पार- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कि इस साल हमारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और सभी के सामूहिक प्रयासों से हमने इस लक्ष्य को पार कर लिया है और अब तक 10 करोड़ 21 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा काल अभी चल रहा है, ऐसे में विभाग इस अभियान के तहत लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। श्री शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेशवासियों की पर्यावरण

के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आमजन से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की अणील की।

विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का हो रहा विकास-स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने इस अवसर पर सभी अध्यापक एवं विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि “हरियालो राजस्थान” केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य से किया गया वादा है। जिस प्रकार 4.15 करोड़ पौधारोपण का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल हुआ है, उसी तरह यदि हर नागरिक एक पौधे को जीवनभर संजोने का संकल्प ले, तो राजस्थान निश्चित ही हरियाली की नई मिसाल बनेगा। उन्होंने अपील कर कहा कि हम सब मिलकर यह प्रण लें – एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आने वाली पीढ़ी के नाम लगाएँ। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत न केवल विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा बल्कि शिक्षा विभाग और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान में हरित आवरण में भी वृद्धि होगी, वहीं

तकनीक आधारित पारदर्शी रिपोर्टिंग और सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

गौरतलब है कि इस अभियान के तहत सभी पौधों को जियो टैगिंग के माध्यम से हरियालो राजस्थान ऐप पर दर्ज किया जा रहा है ताकि पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी सतत प्रयास किये जा सकें, साथ ही ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आंकड़ों की पारदर्शिता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक स्कूल की अभियान से जुड़ी गतिविधियों की रिपोर्टिंग शाला दर्पण एप के माध्यम से की जा रही है। वहीं विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय स्तर की भागीदारी को सुनिश्चित कर विद्यालय-वार पौधारोपण प्रगति की डिजिटल ट्रैकिंग भी निरंतर की जा रही है। “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” के तहत शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण ऐसी पहल है, जो शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखती बल्कि प्रकृति और समाज से भी जोड़ती है। अभियान के तहत विद्यालयों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और राजस्थान को हरित राजस्थान बनाने में योगदान दें।

—डॉ. अमृता कटारा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, डीआईपीआर, जयपुर

आत्मा के स्वाभाविक धर्म : दशलक्षण धर्म विश्वशांति का उद्घोषक



भागचंद जैन मिश्रपुरा

जैन धर्म अनादि, अनंत, शाश्वत, सनातन धर्म है। इस युग के जैन धर्म प्रवर्तक वर्तमान अवसरपिणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं। जैन धर्म के तीन प्रमुख पर्व वर्ष में तीन बार मनाए जाते हैं। 1) षोडश कारण भावना पर्व का पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव (बंधन) होता है। 2) अष्टाष्टिका पर्व सिद्धों की भक्ति का पर्व मनाने से आत्म शुद्धि होती है एवं 3) – दशलक्षण पर्व– इस पर्व को बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद में आने वाले इस पर्व के दौरान आत्मा के दस धर्मों की विशेष आराधना करते हैं। दस धर्मों का पालन करना साधकों, तपस्वियों के मूल गुण है। श्रावकगण भी आत्म कल्याण के दस धर्मों का पालन करने की चेष्टा करते हैं। दशलक्षण पर्व आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है, इसकी पर्वराज भी कहा जाता है। जैन धर्म में इस पर्व का महत्वपूर्ण स्थान है।

दशलक्षण धर्म पर्व, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, में दस धर्मों की पूजा, आराधना एवं पालना की जाती है, वे दस धर्म इस प्रकार हैं:

- 1) उत्तम क्षमा: दूसरों को क्षमा करना और स्वयं की गलती के लिए दूसरों से क्षमा मांगना।
- 2) उत्तम मार्दव : विनयशील, विनम्र, कोमल भाव रखना।
- 3) उत्तम अर्जुनः मन की शुद्धता, सरलता बनाए रखना एवं छल-कपट से दूर रहना।
- 4) उत्तम शौच : पवित्र भावना एवं मन, वचन और शरीर की शुद्धि रखना।

5) उत्तम सत्य : सच बोलना और सच का पालन करना ही सत्य धर्म नहीं है। आत्मा से जो शांति स्वरूप वीतरागता उत्पन्न होती है, वहीं सत्य धर्म है।

6) उत्तम सम्यग् : अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अर्थात आत्म नियंत्रण प्राप्त करना।

7) उत्तम तपः आंतरिक एवं बाह्य 12 प्रकार के तप धारण कर कर्मों का नाश करना।

8) उत्तम त्याग : वास्तविकता में त्याग से प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, देने के सुख का अनुभव होता है।

9) उत्तम अकिंचनः वस्तुओं और व्यक्तिवों से आसक्ति न रखना।

10) उत्तम ब्रह्मचर्यः अपने आत्म स्वरूप में रमण करना।

इन दस धर्म में से प्रथम तीन लक्षण भाव धर्म, आगे के पांच लक्षण मोक्ष मार्ग प्राप्ति के उपाय एवं अंतिम दो लक्षण धर्म का सार है।

इनकी पालना कर आत्म शुद्धि की जाती है एवं आत्मानुशासन की ओर अटसरत होते हैं। इन सभी धर्मों के अंगुर्गुण नाम से ही स्वतः स्पष्ट है। ये सभी धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी एक धर्म की पालना, साधना करने से शेष सभी धर्म आत्मसात हो जाते हैं एवं साधक के जीवन का अंग बन जाते हैं। उत्तम शब्द सम्यक् दर्शन के साथ इन गुणों को प्राप्त करने के अर्थ में लिया गया है। आत्मा के सत्य स्वरूप को प्रकट करने के कारण उत्तम धर्म कहा जाता है एवं उत्तम धर्म ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। यह पर्व जिन मंदिरों में विशेष पूजा के साथ बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान जैन धर्मावलंबी सामान्यतः व्यापार एवं नौकरी से अवकाश पर रहते हैं। इन दस धर्मों में जिन अभिषेक, शांतिहार, पूजा, पाठ, स्वाध्याय यथावत करते हैं। प्रतिदिन नित्य नियम पूजा के साथ सभी दस धर्मों की पूजा विधान है, किंतु महत्ता की दृष्टि से प्रत्येक दिन क्रमशः अलग अलग धर्म के गुणों का विशेष वर्णन सूक्ष्मतम रूप में पूजा करने के अंत आत्मसात् किया जाता है।

इस पर्व में जैन धर्मावलंबी साधना के मार्ग को अपनाते हुए व्रत, उपवास

रखते हैं एवं कई भक्त दस दिनों तक अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते हैं एवं इस पर्व में भोजन करने वाले सात्विक भोजन ही सीमित मात्रा एवं आवृत्ति में ग्रहण करते हैं।

श्रावकगण इस समय का सदुपयोग त्याग, तपस्या, आराधना, साधना का मार्ग अपना कर करते हैं। यह पर्व अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मशुद्धि एवं कर्मों का क्षय कर मोक्षमार्ग प्रशस्त करने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व यथाशक्ति दान देने की प्रेरणा भी देता है। इस पर्व के अंत में जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमावानी पर्व मनाया जाता है।

जीवन को सजीवम तरीके से जीने की कला सिखाने वाले दस धर्मों को व्यवहार में उतारने का पर्व दशलक्षण महा पर्व है। उल्लेखनीय है कि इन दस धर्मों पर जैन धर्मावलंबियों का एकाधिकार नहीं है, कोई भी इन्हें अपनाकर मोक्षमार्ग प्रशस्त कर सकता है। दस धर्मों में आत्मिक शांति के साथ वैश्विक शांति निहित है। अपनाकर तो देखिए। श्वेतांबर संप्रदाय में यह पर्वण्य पर्व के नाम से आद दिन के लिए मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20/08/25 से 27/08/25 तक मनाया गया है।

दस धर्म की पालना क्यों ? भारतीय संस्कृति विचार में निराली है। यहां हर धर्म समाज में सद्भावना बनी रहती है। यहां के त्यौहार तार्किक आधार पर मनाए जाते हैं। उनको अपनाने में प्राणी मात्र के साथ समाज एवं राष्ट्र कल्याण निहित होता है। जीवन किसी भी प्रकार से जिया जा सकता है, लड़ाई झगड़ा करके, सामंजस्य के साथ या सद्भावना यानी एक दूसरे का मंतव्य समझते हुए। भाद्रपद मास में आने वाला दस धर्मों का पर्व भी बहुत सारे संदेश छिपे हुए है। दस दिन तक लगातार जब व्यक्ति भक्ति, पूजा पाठ, स्वाध्याय एवं नियमित रूप से आत्म चिंतन, ध्यान करता है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन वह भी सीमित मात्रा में ग्रहण करता है तो इसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिकता जीने की एक कला है। इस दौरान मुनिसंघों के सानिध्य में विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिक, ध्यान

शिविर लगाए जाते हैं। शिविराष्ट्री इस दौरान उसी स्थान पर रहते हैं। इन शिविरों में सात्विक नियमों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इस पर्व में सभी दश धर्म की विवेचना एवं पालना की जाती है। कोई भी नास्तिक या किसी भी धर्म का मानने वाला नास्तिक भी इन धर्मों से विमुख नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ये धर्म शाश्वत है, सर्व कालीन है।

किसी भी राष्ट्र को उन्नित, शांतिपूर्ण वातावरण से ही संभव है, जो दस धर्म में निहित है। इसे वैश्विक स्तर पर अपनाने से विश्व शांति संभव है। सद्भाव और सामंजस्य, अहिंसा और दया का प्रसार, नैतिक मूल्यों का विकास, माया – कपट और ढोंग का त्याग करने और निष्कपट आचरण करने की शिक्षा, आत्म-चिंतन और आत्म-निरीक्षण का अवसर, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रेरित आदि इन सदगुणों का जब समाज में लोग पालन करते हैं, तो विवाद और संघर्ष कम होते हैं, जिससे सामाजिक शांति और स्थिरता बढ़ती है।

व्याप्त समस्याएँ : एक दूसरे से अवांछित होड़ में परिवार में कई समस्याएँ जन्म लेने लगती हैं।बोल चाल बंद होना, सामंजस्य का आभाव, आर्थिक तंगी, नशा करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, हिंसा, विवाह विच्छेद, बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। इसी तरह का समाज को भी निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि असमानता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, पर्यावरण प्रदूषण बाल विवाह व दहेज प्रथा आदि समस्याएँ समाज के एक बड़े धुन, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्थिक असमानता, ऋण संकट आदि से जूझ रहा है।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना दस धर्म प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मिक विकास का अवसर प्रदान

करता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इन धर्मों की पालना करना कठिन नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, जिन्हें हमारे कर्मों की निर्जरा होती है एवं हमारी आत्मा परम पवित्र बनती है। इन्हें अपनाने से हमारा आत्म विवास जगृत होता है क्यों हम किसी के भी प्रति बदले की भावना नहीं रखते है, ज्यादा पाने की इच्छा नहीं रहती है, करुणा के भाव के कारण हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऐसे विचारों से मानसिक स्थिति सुदृढ़ बनती है एवं काया भी निरोगी बनी रहती है, जो हमें सुख की अनुभूति देता है। इस पर्व के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा आध्यात्मिक शिविर लगान्या जाता है, जिनमें लाखों व्यक्ति सम्मिलित होकर सुख की अनुभूति करते हैं।

दस दिनों तक एक व्यक्ति स्वयं में व्याप्त सद्गुणों का अपना लेता है तो ये गुण परिवार से समाज में एवं समाज से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इनका फैलाव हो जाता है। परिवर्तन एवं सुधार के लिए मात्र एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक परिवार में, समाज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त विरोधाभास मात्र एक व्यक्ति द्वारा दूर हो सकता है। अपने समय में एक तीर्थंकर द्वारा ही सबका उद्धार हो जाता है।अहिंसक एवं क्षमा की प्रवृत्ति दो देशों के बीच हजारों वर्षों से चली आ रही दुश्मनी दूर कर देती है। यूकेन – रूस, इजराइल –लेबनान, गाजापट्टी के बीच शांति का वातावरण तैयार हो रहा है। संवेदन शीलता पनप रही है। करुणा का भाव रखकर एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लगे है।प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की ओर बढ़ने लगे है। अस्थायत ही हमें जीवन मरण से छुटकारा दिलाकर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है।इन सबसे अपराधों का ग्राफ नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। सबमें भाईचारे की भावना विकसित होगी। आपस में सामंजस्य का अवसर मिलेगा। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी।

संकलन –-भागचंद जैन मिश्रपुरा,
अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन बैकर्स फोरम जयपुर

वस्तुतः विपक्ष नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है। दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि। इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई सबूत दिया और न कोई शहादत दी जिससे वे आरोपों को साबित कर सकें।

वे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि अन्य राज्यों में पहले हो चुके चुनावों के बाबत भी हैं। यह भी उल्लेखनीय है और प्रासांगिक भी राहुल गांधी इन्में से किसी राज्य के मतदाता नहीं हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जो शपथ पत्र सबूतों सहित पेश करने को कहा है उसका आधार मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 20(3)(बी) है। जिसमें उल्लेख है कि जो व्यक्ति चुनाव राज्य की मतदाता सूची में मतदाता पंजीकृत नहीं है, यदि वह व्यक्ति चुनाव की मतदाता सूची की वैधता को विंसांगियों के आधार पर चुनौती देता है तो उसे शपथ पत्र सबूतों के साथ देना चाहिये। नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु अभी तक राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, उनमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति (नोटिस देने वाला) उत्तर नहीं देता है तो यह माना जावेगा कि उसके आरोप गलत हैं।

पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उक्त नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति यदि विंसंगतियों पर झूठे आरोपों का प्रचार करता है और मतदाताओं की भावनाओं को भडकाता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 191 में विधानसभा की सदस्यता लिये निरर्हतायों (Disqualifications) का उल्लेख है, उसके उप प्रावधान (1)(ई) में उल्लेख है कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरर्हित कर दिया गया हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि मतदाता सूचियों के मामलों में जो व्यक्ति अपराध करता है और उसे 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वह अयोग्य घोषित होगा, तथा यदि वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो स्वतः विधानसभा की सीट संविधान के अनुच्छेद 190 के अनुसार रिक्त घोषित मान ली जावेगी।

वस्तुतः विपक्ष नेता राहुल गांधी का केस है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में गडबडी की है, सही मतदाताओं के नाम काटे हैं जीवित व्यक्तियों को मृतक बना दिया है। दो-दो स्थानों पर नाम दर्ज किये हैं आदि। इस कार्यवाही को वे वोटों की चोरी की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि यह केस चोरी का नहीं है। उन्होंने इस हेराफेरी का न तो कोई सबूत दिया और न कोई शहादत दी जिससे वे आरोपों को साबित कर सकें। इस कारण से राहुल जी से चुनाव आयोग ने रूल 20(3)(बी) के अनुसार शपथ-पत्र देने को कहा था और उन्होंने न तो शपथ-पत्र दिया और न सबूत और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। अतः चुनाव आयोग ने कहा कि उनके आरोप आधार रहित हैं। प्रश्न है चुनाव आयोग अब क्या कदम उठाता है, यह हमें देखना है। हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

लेखक का अपना विचार है कि संसद को एक कानून बनाना चाहिए, जिसमें प्रावधान हो कि यदि कोई देश का नागरिक संवैधानिक कर्तव्यों की पालना नहीं कर रहा है तो उसे चुनाव में खडे होने के हेतु क्पेनसपलिट (अयोग्य) करार दिया जावे। अनुच्छेद 51क स्पष्ट करता है भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान की पालना करे उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। प्राणी मात्र के प्रति दया (करुणा भाव) रखे और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे। हिंसा से दूर रहे। क्या चुनू हुये सांसदों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे संसद को अपना कर्तव्य निभाने दें। गत दिनों संसद में जो हुआ है, क्या ऐसा करने के हेतु हमने अपने सांसद चुनकर भेजे हैं। देश हम सबका है, केवल विपक्ष का नहीं है। देश कभी भी बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिक को जो देश में चुस आये हैं, अवैध प्रवासी हैं, उन्हें एक व्यक्ति एक चुनाव के नारे से मतदान में भाग नहीं लेने दे सकता है। मतदाता तो वही होगा जो अनुच्छेद 326 के अनुसार देश का नागरिक है। उसे ही वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

सबको सम्मति दे भगवान् ! –अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

बाइक चोर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने सात साल पुराने मामले में वांछित चल रहे मोटरसाईकिल चोर को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि 8 अक्टुबर 2०18 को फरियादी राहुल ने रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 4 अक्टुबर 2०18 को मोटरसाईकिल से घर से अपने ससुराल बड़ा सोगरिया आया था। फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि मोटरसाइकिल को घर के बाहर खड़ा करके अंदर गया और थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली, जिसके कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, आरोपी की गिरफ्तारी के लिये रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी मम्वस्वरूप मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गुटित टीम ने तकनीकी आधार व मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मोटरसाईकिल चोरी के सात साल पुराने प्रकरण में आरोपी को जिला बारां के थाना अन्ता के पलायता से डिटेल करने में सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पलायता निवासी सोनू माली (३1) को गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गये आरोपी ने मोटरसाईकिल चोरी की घटना को स्वीकार किया है।

ट्रक से 482 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद, एक गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थ तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये नारकोटिक्स ब्यूरो टीम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा राजमार्ग, चित्तौड़गढ़ पर एक ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 482.६30 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। टीम ने कार्यवाही करते हुवे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स के उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई।

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक ट्रक चित्तौड़गढ़ से हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टून बाक्स के नीचे भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा छिपाकर ले जा रहा है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई

आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टून बाॅक्स के नीचे छिपा रखा था मादक पदार्थ

और टीम को रवाना किया गया। गठित टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और वाहन की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद टीम ने हाईवे पर नरपतखेड़ी ओवरब्रिज के पास ट्रक को रोक लिया गया। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि कार्टन बाॅक्स के नीचे अवैध डोडा चूरा छिपा हुआ है। ट्रक की तलाशी लेने पर कुल 482.६30 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद हुआ।

कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद अवैध डोडा चूरा और एक ट्रक को जप्त कर लिया गया है तथा एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा सण्ड कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1९५९ की धारा 17 के अधीन
नोटिस
मुकदमा नम्बर 90/2025
समस्त सम्पत्तिगत व्यक्तियों को (नाम दर्जित तथा विवरण स्थान)
श्री प्रदीप भण्डारी पुत्र श्री महावीर चन्द भण्डारी, 26 आवास/पूछाड़, कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रशासन अधिनियम 1९५९ की धारा 17(2) के अन्तर्गत प्रमाण के "की करनी नाम विकास समिति" गोरखपुरा, कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के दिवसे आदेशन-पत्र दिया है। आदेश धारा 1८ की उप-धारा (2) द्वारा शरत शर्मा कोटो के प्रयोग में उपर्युक्त प्रमाणों जिन्हें श्री जांच की जा रही है, में हिा रखने वाले सम्पत्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से ६० दिव न के भीतर उक्त प्रमाणों के सम्बन्ध में आपत्तिपूर्ण बरि कोई हो प्रस्तुत करें। और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तिपूर्ण प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निष्पत्ति प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रचर मामले में निष्कर्ष अभिव्यक्ति प्रकाश जायेगा। आज दिनांक 2६.०८.2०2५ को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रमाण में आगामी सुनवाई की दिनांक 29.1०.2025 है। लक्ष्मण आयुक्तर, देवस्थान विभाग, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एन-15/क.भू.क./2025/८६4	विज्ञप्ति	दिनांक:-६.8.2025
सर्वे साधारण को जयें विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम उमदेमरांग योजना "देव एनक्लेव ए" खसरा नं. 93 में स्थित भूखंड संख्या 35 के ऑनलाइन नाम हस्तान्तरण हेतु व्यास कार्यालय में श्रीमती दीपिका हाड़ा पत्नी श्री शम्भू सिंह नरका निवासी 9/91 गोंबिये नगर रेलवे लाईन के पास कोटा राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूखंड संख्या 35 का पट्टा क्रमांक 1116 दिनांक 01.04.2022 को श्री भरत राम गोयेल पुत्र श्री विमलचन्द्र गोयेल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा भूखंड संख्या 35 का बेचान जयें पंजीकृत मुखाल आम श्री फेजान खान पुत्र श्री इमामुद्दीन जयें रजि. क्रियत्र पत्र दिनांक 29.12.2023 से श्रीमती दीपिका हाड़ा पत्नी श्री शम्भू सिंह नरका को कर दिया गया है। अतः श्रीमती दीपिका हाड़ा पत्नी श्री शम्भू सिंह नरका के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योदाहतराकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा		

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर

क्रमांक:-ननिको. (उ.)/प.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2025/11028-29

दिनांक: 26.8.25

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदन की महेश कुमार पुत्र स्व. श्री नंदकिशोर निवासी-331, सुभाष नगर, अन्तर्गुप्त कोटा राज के द्वारा आवास/पूछाड़ जालखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा नगर दिनांक 26.07.1995 को किया गया उक्त आवास का पंजीयन श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती द्वारा दिनांक 07.10.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उन्तरीत श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती द्वारा उक्त आवास का बेचान जयेंर विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 18.06.2012 को श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भारत भूषण गुप्ता को किया गया। श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भारत भूषण गुप्ता का नाम दिनांक 15.04.2025 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में दर्ज किया गया। लक्ष्मणान्त श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती द्वारा उक्त आवास का बेचान जयेंर विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 24.04.2025 को श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल को किया गया। श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिकेन्द्र वस्तुतः कर आवास संख्या 1-एन-20 तलवारी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अफिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल के नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक/ 1419

जाहिर आम सूचना

दिनांक - 2६.8.25

आवास संख्या 1-एस 20 तलवारी, कोटा का आवेदन मण्डल कोटा की मन्दत लाल पुत्र श्री कृष्ण चंद को किया गया था। इस आवास का निवामितिकरण श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती के नाम दिनांक 2६.०7.199५ को किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती द्वारा दिनांक ०7.1०.199५ को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उन्तरीत श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती द्वारा उक्त आवास का बेचान जयेंर विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 1८.०६.2०12 को श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भारत भूषण गुप्ता को किया गया। श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री भारत भूषण गुप्ता का नाम दिनांक 1५.०4.2०25 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में दर्ज किया गया। लक्ष्मणान्त श्री रमेश कुमार मालती पुत्र श्री सुरेश कुमार मालती द्वारा उक्त आवास का बेचान जयेंर विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 24.०4.2०25 को श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल को किया गया। श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिकेन्द्र वस्तुतः कर आवास संख्या 1-एन-2० तलवारी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अफिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 1५ दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अफिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती उमा पत्नी श्री लोकेश गोयल के नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

हत्या के आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया

- हत्या कर शव को खेत में दीवार के पास फेंककर हुआ था फरार**
- शराब पार्टी में कहासुनी होने पर हत्याकांड को अंजाम दिया था**

टीम मौके पर पहुंची तो मृत व्यक्ति के मुंह व शरीर पर चोटों के निशान थे, मौके पर ही डोग स्व्वायल व एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कराई गई। शहर एसपी ने बताया कि मृतकी की पहचान मध्मदेश के पतलीखेड़ी हाल खारी बावड़ी निवासी गोपाल सिंह (40) के रूप में हुई, पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि एक मजदूर अभिजीत राय की टांपरी में खून से सने बिस्तर व टुटे हुए कांच मिले एवं सामने आया कि उक्त व्यक्ति अभिजीत राय भी घटना के बाद से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। शहर एसपी तेजस्वी गौतम ने

कोटा, (निसं)। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बाढ़ प्रभावित किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज देने के साथ जिले को आपदाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग की। जिला मंत्री रूपनारायण यादव ने बताया कि भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें बूजराज नागर कोटा महानगर अध्यक्ष, माणक चंद यादव महानगर मंत्री, रूपनारायण यादव जिला मंत्री, कमलेश महानगर प्रचार प्रमुख, महेंद्र नागर महानगर उपाध्यक्ष, हरिराज सिंह जेलोपा आदि के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार सिंहल को आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

जिलाध्यक्ष जगदीश कलमंडा ने बताया कि आज भी किसान वह दृश्य याद करके रो पड़ते हैं। बाढ़ के निशानों का सब कुछ छीन लिया कुछ रोते हुए किसान कहते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया और मकान टूट गए, जानवर बह गए, जानवरों का चारा बह गया, हमारा गेहूं लहसुन सोयाबीन जो हमारे भंडार में भरे हुए थे वह सब कुछ बाढ़

केडीए अध्यक्ष ने शम्भूपुरा एकीकृत योजना लॉन्च की

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त एवं कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पीयूष समारिया ने गुरुवार को केडीए की शंभूपुरा एकीकृत योजना (व्यावसायिक गोदाम एवं व्यावसायिक होलसेल मार्केट योजना) लॉन्च की। इस योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंड हैं। इसमें ब्लॉक ए गोदाम के लिए 129 व्यावसायिक भूखंड जबकि ब्लॉक बी में होलसेल मार्केट के लिए 222 व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध हैं। योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंडों के विक्रय से केडीए को करीब 1३7 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। भूखंडों का आवंटन केडीए द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

शंभूपुरा एकीकृत योजना कोटा-बूंदी एक्सप्रेस के समीप तथा हौरिंग ब्रिज से 4.८ किलोमीटर की दूरी, कोटा-चित्तौड़गढ़ रोड (नेशनल हाईवे-27) से आधा किलोमीटर की दूरी तथा कोटा-जयपुर रोड़ (नेशनल हाईवे-५2) से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केडीए द्वारा योजना के समीप ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रक रिपेयर वर्कशॉप, नगर योजना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आवासीय योजना, पार्क एवं अन्य आवासीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

योजना को लॉन्च करते समय केडीए अध्यक्ष समारिया ने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के समीप होने से काफी महत्वपूर्ण है और कोटा शहर के लिए प्राधिकरण की ओर से बड़ी सीगात

बताया कि युवक की हत्या के मामले का खुलासा करने एवं आरोपी को गिरफ्तारी के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल के सुपरविजन में बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में टीम गठित की गई। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम को घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों जिसमें अभिजीत राय की टांपरी में मिले खून के धब्बों व कांच के टुकड़ों से अभिजीत राय पर शक हुआ।

पुलिस टीम ने घटना स्थल के आस-पास कार्यरत मजदूरों से पूछताछ की, घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम के अनुसंधान के दौरान मृतक गोपाल सिंह व अभिजीत राय को सीसीटीवी फुटेज में एक साथ देखा गया जिस पर अभिजीत राय के खिलाफ प्रथम दृष्टया से अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस टीम ने अभिजीत राय के बारे में जानकारी जुटाई। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को जानकारी में अभिजीत राय के पश्चिम बंगाल का निवासी होने की जानकारी

मिली, जिस पर आरोपी की तलाश के लिये एक टीम पश्चिम बंगाल रवाना की गई। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने अथक प्रयास करते हुए आरोपी को पश्चिम बंगाल के गांव बोलमारी से डिटेल कर गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को कोटा लाया गया। पुलिस टीम ने गोपाल सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल के बोलमारी गांव निवासी अभिजीत राय उर्फ अरजजीत राय (३1) को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार किया।

मामले में आया सामने-शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि 30 अक्टूबर 2023 को उसकी टांपरी में बैठकर उसने व गोपाल सिंह ने साथ बैठकर शराब पार्टी की। शराब पार्टी में कहासुनी होने पर आरोपी ने गोपाल सिंह की हत्या कर दी और लाश को देवाशीष सिटी के पीछे खेत में पत्थरों की कोटनुमा दीवार के पास फेंककर फरार हो गया और गिरफ्तारी के डर से अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग स्थानों पर फरारी काट रहा था।

शक्तावत सर्वसम्मति से संरक्षक चुने गए

रामगंजमंडी, (निसं)। कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की

- कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक हुई**

गुरूवार को एसोसिएशन भवन कुदायला में सामान्य बैठक हुई। बैठक में पूर्व अध्यक्ष व पथर व्यवसायी जगदीश सिंह शक्तावत को सर्वसम्मति से संरक्षक चुना गया। इससे पूर्व शक्तावत इस एसोसिएशन के वर्ष 2००1 से 20०7 तक उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

 पश्चिम मध्य रेल
 सिग्नल एवं दूर संसार सिग्नल – बुद्धि-पत्र टैडर सं. Kola/SNT/SIG/2025/19 दिनांक: 11.०8.2०25
निविदा सूचना संख्या Kola/SNT/SIG/2025/19 की दिशि पत्र निम्न टैडर जो निविदा संख्या Kola/SNT/SIG/2025/19 को दिनांक 11.०8.2०25 के अंतर्गत आमंत्रित किया गया था। अब प्रशासनिक कारणों से इनके खुलने की तिथि एवं कार्य की अनुमानित लागत में परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार हैं- टैडर सं. कोटा/एसएण्टडी/सिं./, 2025/1९, कार्य का नाम- एनुअल मेन्टीनेन्स कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ डाटा लीगंस इंस्टॉल ऑन कोटा डिवीजन (202५), पुरानी तारीख एवं समय- दिनांक 02.०9.2०2५ को 15:०० बजे तक, परिवर्तित तारीख एवं समय- दिनांक 12.०9.2025 को 15:०० बजे तक, (हरता)
वरि. मं. सं. एवं दू. सं. इंजी (समन्वय) परिचय मध्य रेल, कोटा
 पश्चिम मध्य रेल
 मुख्य कारखाना प्रबन्धक माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा
निविदा सं. M-324-Wagon Body-Ten-01RE भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं जनकी और से मु.का.प्र. माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा निम्नलिखित कार्य की ई-निविदा आमंत्रित करते है: टैडर सं. M-324-Wagon Body-Ten-01RE, कार्य का विवरण: माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा प.म.रे. में माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील (बॉक्सएन और बीसीएन टुप) वैगनों में बॉडी मरम्मत के कार्य की आउटसोर्सिंग जिसमें 12 महीने की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा बेल्डिंग मशीनों की व्यवस्था भी शामिल है। अनुमानित लागत रु में: रुपये ६,६६,7९,200.००/-, निविदा प्रपत्र राशि रु में: निं.।
बायाना राशि रु में: रुपये 4,८3,400.००, कार्य पूर्ण करने की अवधि: 12 माह, निविदा बंद/खोलने की तारीख और समय: बंद होगा 11:3० बजे दिनांक 2५.०9.202५ एवं खोला जाएगा 12:०० बजे दिनांक 2५.०9.2०2५ ई-निविदा वे बसाईट https://www.ireps.gov.in इन पर अपलोड की गई है तथा मुख्य कारखाना प्रबन्धक कोटा के प्रगति अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है ऑफर सिर्फ ई निविदा के माध्यम सिर्फ ई निविदा के माध्यम से इसी वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेंगे। इस निविदा के लिये मैनउअल ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि ऐसे कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।
उप मुख्य यांत्रिक इंजी.-II
मा.हि.म. कारखाना, परिचय मध्य रेलवे, कोटा
 स्व्ख भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि स्थानीय व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के आगे विस्तार की प्लानिंग भी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। केडीए आयुक्त हरफूल यादव ने लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि यह योजना कोटा-चित्तौड़ी, कोटा-जयपुर रोड के करीब होने से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लॉन्चिंगके सोल्यूशन पहले से ही उपलब्ध है। व्यवसायी वर्ग में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है।

केडीए अध्यक्ष पीयूष समारिया एवं कोटा आयुक्त हरफूल यादव ने इस अवसर पर योजना की बुकलेट भी रिलीज की। साथ ही, योजना के प्रचार-प्रसार के लिए गाड़ी को रीी झंडी दिखकर रवाना किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएस आरधना चौहान, केडीए सचिव कुशल कोटारी, उप सचिव (भूमि अविपत्ति) मालविका त्यागी, निदेशक वित्त नीतू सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी सहित माधु, पीएनबी के मंडल प्रबंधक रहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। योजना के तहत आवेदन फार्म गुरुवार से मिलना प्रारंभ हो गए। आवेदन पंजाब नेशनल बैंक कोटा की समस्त शाखाओं, केडीए परिसर के काउंटर तथा अन्य जिलों में जिला मुख्यालय पर पीएनबी की नोडल शाखा से 5०० रुपये शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किया जा सके। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2०25 होगी।

नाम परिवर्तन
मेरी पुत्री हीया चौधरी के जन्म प्रमाण पत्र में माता के रूप में मेरा नाम लता के नाम से अंकित है। जबकि अन्य दस्तावेजों में लता चौधरी अंकित है दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। भविष्य में मुझे लता के नाम से जाना जाए।
पता- लता चौधरी अति नशक कोटा चौथी 1० बी 32 महावीर अशोक कोटा

खोया पाया
मेरे मकान संख्या 1-ग-1० दादाबाड़ी का मूल कब्जा पत्र एवं इन्वेन्ट्री कही खो गई है मिलने पर सम्पर्क करें।
रचना मल्होत्रा
1-ग-1० दादाबाड़ी

अवैध पिस्टल सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। दादाबाड़ी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार पिस्टल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल

यादव ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर इलाके के गौतम वाटिका के समीप पहुंचकर कार्यवाही करते हुए जिला बूंदी मोड़ीपाडा बाईपास निवासी सोयल उर्फ

फट्टर (21) की तलाशी के दौरान अवैध हथियार पिस्टल बरामद की। टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम
नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत नवनेरा बैराज के डिलीवरी सिस्टर्न से मेज नदी के मराव तक सभी संरचनाओं सहित फीडर एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण में कोटा एवं बून्दी जिले की भारत सरकार द्वारा जारी सेधान्तिक स्वीकृति वन भूमि प्रत्यावर्तन (Online Proposal No.:-FP/RJ/WATER/504909/2024) दिनांक ०3.०6.2025
 आम सूचनार्थ Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office, Gandhinagar, 3rd Block, 5th Floor, F2, Sector -10a, Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)- 382010 Email: iro.gandhingr mefca@gov.in, Tel No. +९17९-2९६13९51
Online Proposal No.: FP/RJ/WATER/504909/2024
To,
Principal Secretary (Forest and Environment), Department of Forest and Wildlife Government of Rajasthan, Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)
Subject:
Diversion of 24.05 ha. of Protected Forest land for the Construction of feeder with all structures from delivery cistern at Navnera barrage to submergence of Mez Anycut including construction of aqueduct for crossing of Chambal river (NGBI link package 2) in Kota & Bundi Districts of Rajasthan in favour of Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/WATER/504909/2024).

Sir/Madam, I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/WATER/504909/2024 dated 07/11/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1९८० and to say that the proposal has been examined by **Regional Empowered Committee** in its 25 Meeting held on 30.05.2025. After careful consideration and approval of the proposal by the 25th REC, the undersigned is directed to convey the **"In-Principle/Stage-I"** approval of the Central Government under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1९८० for the proposal for non-forestry use of 24.05 ha of Protected Forest land for the Construction of feeder with all structures from delivery cistern at Navnera barrage to submergence of Mez Anycut including construction of aqueduct for crossing of Chambal river (NGBI link package 2) in Kota & Bundi Districts of Rajasthan in favour of Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited, Rajasthan subject to the fulfilment of the following general, standard and specific conditions:

1. General Conditions	
S.no	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The non-forest land identified for raising compensatory afforestation shall be transferred and mutated in favour of the state forest department before issue of the stage II clearance
1.3	The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the state Government as RF under Section-4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(5) of the local Forest Act, 1927 latest within a period of six months from the date of issue of Stage-II approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record
1.4	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.5	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.6	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency. Or Compensatory afforestation over the non-forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency
1.7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.8	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.9	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.10	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1९८६, if required
1.11	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.12	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the Stale Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.13	No labour camp shall be established on the forest land
1.14	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.16	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.18	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.19	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.20	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2००६, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoF
1.21	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project

1.22	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1 st January and 1 st July
-------------	---

डीजीजीआई टीम ने भीलवाड़ा में दस से अधिक स्थानों पर दबिश दी

छापेमारी की मुख्य कार्रवाई निखिल डाड, जो पूर्व भाजपा ज़िलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड के पुत्र हैं, के ठिकानों पर भी की गई

भीलवाड़ा, (निसं)। जीएसटी कर अपवंचन की जांच को आगे बढ़ाते हुए महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस, जयपुर जोनल यूनिट की टीमों ने गुरुवार को भीलवाड़ा में दस से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। जयपुर से आई कई विशेष टीमों ने भीलवाड़ा में फैले विभिन्न प्रोसेस हाउस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी। यह कार्रवाई जीएसटी चोरी एवं फर्जी बिलिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से की जा रही है। छापेमारी की मुख्य कार्रवाई निखिल डाड, जो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड के पुत्र हैं, के ठिकानों पर भी की गई। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान तलाशी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं, जिनका विभागीय स्तर पर विश्लेषण किया जाएगा। डीजीजीआई की यह समन्वित कार्रवाई राज्य में चल रहे जीएसटी कर चोरी के मामलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।



डीजीजीआई जयपुर की टीम ने भीलवाड़ा में दस से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।

अब तक दस्तावेजों की जांच में 10 करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी सामने आई है, साथ ही माहेश्वरी केमिकल से अनुज सोमानी का भी नाम सामने आया है, जिसके ठिकानों

पर भी जांच में जुटी है। इधर, निखिल डाड केमिकल, कोयला, प्रॉपर्टी और फाइनेंस का कारोबारी है। भीलवाड़ा के कई नामचीन व्यक्तियों की पार्टनरशिप इसके अलग अलग धंधों

- जयपुर से आई कई विशेष टीमों ने भीलवाड़ा में फैले विभिन्न प्रोसेस हाउस और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी
- यह कार्रवाई जीएसटी चोरी एवं फर्जी बिलिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से की जा रही है
- अब तक दस्तावेजों की जांच में 10 करोड़ से अधिक की जीएसटी कर चोरी सामने आई, साथ ही माहेश्वरी केमिकल से अनुज सोमानी का भी नाम सामने आया

में बताई जा रही है। इस कंपनी के क्लाइंट बड़े-बड़े प्रोसेस हाउस हैं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में डीजीजीआई की कार्रवाइयों भीलवाड़ा में बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर में महावीर ट्रेडिंग कंपनी सिंडिकेट के खिलाफ 706 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की मामला सामने आया था। यहां तक कि सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जीएसटी नंबर, नकली बिल, हवाला

ट्रांजेक्शन और बिना ई-वे बिल के माल परिवहन जैसी गंभीर अनियमितताएं मिली थी। उसके बाद 21 अगस्त को रत्नाकर ग्रुप के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 50 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की बात सामने आई थी। इस कार्रवाई के अंतिम दौर में रत्नाकर ग्रुप की ओर से करीब 20 करोड़ रुपए टैक्स पैन्लटी के रूप में जमा कराए थे।

कपिल सरोवर में डूबने से युवक की मौत

बीकानेर, (निसं)। जयपुर से बीकानेर होकर रामदेवरा जा रहे एक यात्री की कपिल सरोवर में डूबने से मौत हो गई। वो सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा था, लेकिन पैर फिसलने के कारण सरोवर में डूब गया। एसडीआरएफ टीम ने सरोवर से निकालकर युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

- जयपुर से बीकानेर होकर रामदेवरा जा रही बस का यात्री था, रास्ते में नहाने उतरा था

पहुंची तथा युवक को दूढ़ने का प्रयास किया। करीब एक घंटे बाद एसडीआरएफ टीम द्वारा शव को बरामद कर लिया गया। कोलायत पुलिस थाने में अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। मर्ग के आधार पर ही पुलिस जांच करेगी। एसडीआरएफ टीम में एसडीआरएफ टीम में हेड कॉन्स्टेबल रामेश्वर लाल, बाबूलाल, केशाराम, भंवरदास, पप्पूराम, प्रेमराम, लालचंद, श्रवण, नरेन्द्र, शशिकांत, नरेश, विजेंद्र आदि मौजूद थे।

लूणी नदी में बहे लोगों में से एक का शव मिला

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा के निरमट लूणी नदी की रफ्तार करके समक आठ श्रद्धालुओं को घटने जा रही एक बोलोरो बह गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन के निर्देशन में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और नागरिक सुरक्षा बल की टीमों ने तुरंत एक बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू किया। निरंतर चले इस ऑपरेशन में बचाव दल को एक बड़ी सफलता मिली। टीमों ने प्रयासों के बाद नदी से एक शव बरामद कर लिया है।

हालांकि अभी भी दो अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है और बचाव अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. गुंजन सोनी, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार और तहसीलदार गोपीकिशन पालीवाल भी लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं।

RAJMATI VIJYARAJE SINDHIYA
KRISHI UPAJ MANDI SAMITI (G) JODHPUR
E-mail id : www.krishimandi@yahoo.in / kums.jodhpur@rajasthan.gov.in
Tel. :- 0291-2571999 Fax :- 0291-2570754

E-Tender Invitation Notice No. 10/2025-26
Under the Rajasthan Public Procurement Transparency Act 2012 and Rules 2013, on line tender is invited through e-procurement from service providers/registered contractors/cooperative institutions/voluntary institutions/ex-servicemen cooperative institutions etc. within the approved budget for Supply of workers for computer work in Rajmata Vijayaraje Sindhiya Krishi UPAJ Mandi Samiti (Grain) Jodhpur, regarding procurement of human resources services, till 10.00 am on 10-09-2025 The detailed information related to tenders can also be seen on www.sppp.rajasthan.gov.in, www.agriculture.rajasthan.gov.in and www.eproc.rajasthan.gov.in UBN : DAM2526SL0B00704
1. Supply of workers for computer work in Rajmata Vijayaraje Sindhiya Krishi UPAJ Mandi Samiti (Grain) Jodhpur
Raj.Samwad/C/25/8936

राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आर्युविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर
मेडिकल कॉलेज रोड, बीकानेर 334001 फोन-0151-2226300
Email-principal spmc bknr@rajasthan.gov.in

क्रमांक प... (क्रयपत्र प्राप्त) साप्ताहिक/Tender/2025-26/696 दिनांक-15.08.2025

ई-बोली संख्या 03 (2025-26)
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से उपोद्घोषावर्कवा द्वारा R.T.P.P. Act 2012 तथा R.T.P.P. Rules 2013 नियम के तहत सरदार पटेल आर्युविज्ञान महाविद्यालय व संबंधित चिकित्सालय हेतु Hospital Management Information System and Tele-Consultations योजना-नर्तक कम्प्यूटर नेटवर्क, टैबलेट, प्रिंटर स्कैनर एवं एवं स्थापित करने के लिए खुली प्रतियोगिता बोली (द्वि भाग बोली तकनीकी एवं वित्तीय) के माध्यम से (as per Bid Documents) ई-बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है। जिसमें इच्छुक बोलीदाता द्वारा ई-प्रोक्त के माध्यम से बिड डीमॉन्स्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज डाउनलोड कर ई-बोली के दस्तावेजों अनुसार ऑनलाईन अपलोड कर ई-बोली में भाग ले सकते हैं।
बोली से संबंधित विवरण DIPR की वेब साइट एवं sppp.rajasthan.gov.in and eproc.rajasthan.gov.in पर एवं सरकारी वेब साइट पर नॉटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
NIB CODE- MCB2526A0090, UBN NO.- MCB2526GL0B00114
प्रधानाचार्य एवं निर्यंत्रक सरदार पटेल आर्युविज्ञान महाविद्यालय सन्मन्ड चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

DIPR/C/12221/2025

बाड़मेर में तीन मादक पदार्थ तस्करों की 2.50 करोड़ की संपत्ति फ्रीज़

कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर गोरधनराम जाट, श्याम सुंदर सांवरिया, जसवंत उर्फ जसराज उर्फ जसू की संपत्ति फ्रीज़ की

जयपुर/बाड़मेर। मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ बाड़मेर पुलिस ने एक बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली बार पुलिस ने एक साथ तीन कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों की अवैध रूप से अर्जित की गई 2.50 करोड़ की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2)



बाड़मेर पुलिस ने तस्करों की संपत्ति फ्रीज़ करने की कार्रवाई की।

- कार्रवाई में तीन आलीशान आवासीय भवन, दो प्लॉट और चार लज्जरी वाहन जब्त किए

कमर तोड़ना है। गोरधनराम जाट की 60 लाख की संपत्ति फ्रीज़ :-नागणा पुलिस थाने का हाईकोर अपराधी गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था। उसकी अवैध कमाई पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। थानाधिकारी जमील खां के नेतृत्व में टीम ने गोरधनराम की संपत्तियों का गहनता से ब्यौरा जुटाया। यह पाया गया कि उसने अपने गांव मातासर भुरटिया में एक आलीशान भवन बनाया था। सभी दस्तावेजों को

सक्षम प्राधिकारी को भेजने के बाद गोरधनराम की लगभग 60 लाख की संपत्ति को फ्रीज़ करने का आदेश मिला। उसके खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज हैं।

श्याम सुंदर सांवरिया की 90 लाख की संपत्ति फ्रीज़ :-सेड़वा थाना क्षेत्र के सक्रिय तस्कर श्याम सुंदर सांवरिया पुत्र लाधुराम पर 13 मामले दर्ज हैं, उसकी भी करीब 90 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। थानाधिकारी दीपसिंह की टीम ने सूचनाएं एकाग्रित कर पाया कि श्याम सुंदर ने अपने गांव

सोमारड़ी में एक भव्य आवासीय भवन और चार वाहन एक स्कॉर्पियो, एक टवेरा, एक ट्रैक्टर और एक बोलोरो कैपूर खरीदे थे। इन सभी संपत्तियों को फ्रीज़ करने के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

जसवंत उर्फ जसराज उर्फ जसू की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज़ :-रीको थाना के हाईकोर अपराधी जसवंत उर्फ जसराज उर्फ जसू पुत्र रतनाराम बायतु पनजी का निवासी है और वर्तमान में बलदेव नगर में रह रहा था, उसकी 1 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। थानाधिकारी मनोज सामरिया की टीम ने पाया कि जसवंत ने बाड़मेर के बलदेव नगर में अपनी पत्नी के नाम पर एक आलीशान घर और दो रिहायशी प्लॉट खरीदे थे। जसवंत पर 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। सक्षम प्राधिकारी से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने उसकी सभी संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मोना ने कहा है कि बाड़मेर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त सभी अपराधियों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी।

पालिका का कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीकर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के कनिष्ठ सहायक दिव्य प्रकाश चौमाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है।

- सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी

जगह पर निर्माण स्वीकृति के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाहने के लिए नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में 12 अगस्त को सूचना के अधिकार के पास मनोहर जलाशय की भूयाफिया द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर निर्माण कार्य कर दुकाने बनावे जा रही है। परिवदाी द्वारा नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ से प्यार की

बनास नदी में दो बालिकाएं डूबीं

भीलवाड़ा, (निसं)। बड़लियास थाना क्षेत्र में बनास नदी में दो बालिकाओं के डूब जाने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हादसा आकोला और नाहरगढ़ के बीच नदी के गहरे पानी में हुआ है। गुरुवार को नाहरगढ़ निवासी अंशु केवर और तनु सेन बनास नदी में नहाने गई थी। इस दौरान नदी में बहाव तेज हो जाने की वजह से बालिकाएं बह गईं। बताया जा रहा है कि मातृकुंडिया बांध से छोड़ा गया पानी नदी के इस हिस्से में पहुंचा था जिससे जलस्तर बढ़ गया और हादसा हो गया।

राजस्थान सरकार

प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आर्युविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर
मेडिकल कॉलेज रोड, बीकानेर 334001 फोन-0151-2226300
Email-principal spmc bknr@rajasthan.gov.in

क्रमांक प... (क्रयपत्र प्राप्त) साप्ताहिक/Tender/2025-26/696 दिनांक-15.08.2025

ई-बोली संख्या 03 (2025-26)
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से उपोद्घोषावर्कवा द्वारा R.T.P.P. Act 2012 तथा R.T.P.P. Rules 2013 नियम के तहत सरदार पटेल आर्युविज्ञान महाविद्यालय व संबंधित चिकित्सालय हेतु Hospital Management Information System and Tele-Consultations योजना-नर्तक कम्प्यूटर नेटवर्क, टैबलेट, प्रिंटर स्कैनर एवं एवं स्थापित करने के लिए खुली प्रतियोगिता बोली (द्वि भाग बोली तकनीकी एवं वित्तीय) के माध्यम से (as per Bid Documents) ई-बोली आमंत्रण सूचना जारी की जाती है। जिसमें इच्छुक बोलीदाता द्वारा ई-प्रोक्त के माध्यम से बिड डीमॉन्स्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज डाउनलोड कर ई-बोली के दस्तावेजों अनुसार ऑनलाईन अपलोड कर ई-बोली में भाग ले सकते हैं।
बोली से संबंधित विवरण DIPR की वेब साइट एवं sppp.rajasthan.gov.in and eproc.rajasthan.gov.in पर एवं सरकारी वेब साइट पर नॉटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
NIB CODE- MCB2526A0090, UBN NO.- MCB2526GL0B00114
प्रधानाचार्य एवं निर्यंत्रक सरदार पटेल आर्युविज्ञान महाविद्यालय सन्मन्ड चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

DIPR/C/12221/2025

राजस्थान सरकार

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांक वि.सं.09/Exam/School Leet.(Agriculture)/RPSC/EP-1/2025-26 दिनांक-28.08.2025
आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अग्रोनेश्वर) सेवा नियम 2021 के अन्तर्गत प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा) के कुल 5000 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शोकानिक योग्यता आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विवरण का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है:-
आयु सीमा दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
आवेदन अवधि दिनांक 04.09.2025 से दिनांक 03.10.2025 रात्रि 12.00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में क्यासमय सूचित कर दिया जायेगा।
अन्य विन्दु व सूचना-एकवारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नीतिनम एवं संगोपित परीक्षापत्रों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निदेशन/सूचना/स्वीकृति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.-0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।
रामनिवास मेहता, सचिव

DIPR/C/12471/2025

की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी झुंझुनूं टीम को परिवदाी ने शिकायत दी कि लक्ष्मणगढ़ कस्बा में गणेश जी के मन्दिर के पास मनोहर जलाशय की भूयाफिया द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर निर्माण कार्य कर दुकाने बनावे जा रही है। परिवदाी द्वारा नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ से प्यार की

जगह पर निर्माण स्वीकृति के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाहने के लिए नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में 12 अगस्त को सूचना के अधिकार के पास मनोहर जलाशय की भूयाफिया द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर निर्माण कार्य कर दुकाने बनावे जा रही है। परिवदाी द्वारा नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ से प्यार की

नदी के तेज बहाव में बहा शिक्षक, तलाश जारी

उदयपुर, (कासं)। सलुंवर जिले में गुरुवार को नदी से गुजरते तेज पानी के बहाव में एक बाइक सावधानी पानी में बह गया। बचाव दल को उसकी बाइक तो मिल गई है, लेकिन बाइक सवार अभी तक नहीं मिला, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार सलुंवर जिले के जलारा समोडा मार्ग पर पायरा गांव के निवासी शिक्षक नीरभद्र सिंह समोडा, स्कूल के लिए निकले थे। वे अपनी बाइक से जैसे ही जलारा समोडा मार्ग पर बने पुल से गुजरे अचानक तेज बहाव ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत तलाश शुरू कर दी। खोज अभियान के दौरान नदी में शिक्षक की बाइक बरामद हुई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: जविप्रा/व.उ.वि./2025-26/34-36 दिनांक : 28.08.2025

पूर्णकालीन बिड सूचना सं.-जविप्रा/व.उ.वि./2025-26/34-36

आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्राधिकरण के उद्घाटनिकी प्रवर्ग की उचित श्रेणी में पंजीकृत बोलीदाताओं एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को सभी विभागों में 'अ'अ' व 'अ' श्रेणी में पंजीकृत बोलीदाताओं से ई-बिड (E-Procurement) निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

S. No.	NIB No.	Name of Work	Tender Amount (In Lakh)	Sale/Download Date and End Date	Open Date	Job No.
1	34	Maintenance & Management of Kishan Bagh, Native Plants Biodiversity Park, Jaipur for 2 years. UBN No. JDA2526WSOB00405	117.17	29.08.25 08.09.25	11.09.25	171/2025-26
2	35	Development and maintenance of Mahal Road Greenbelt Jagatpura ROB to Jivan Rekha Hospital chorahra for 2 year in H.Zone-I UBN No. JDA2526WSOB00406	181.45	29.08.25 08.09.25	11.09.25	226/2025-26
3	36	Development and maintenance of median and greenbelt in Saraswati Vihar residential scheme for 2 year in H.Zone-II UBN No. JDA2526WSOB00407	180.84	29.08.25 08.09.25	11.09.25	219/2025-26

नोट :-

1. बिड को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
2. बिड E-Procurement के जरिए प्राप्त की जायेगी। बोलीदाता द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. बिड से सम्बन्धित शर्तें वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in, <http://eproc.rajasthan.gov.in>, sppp.rajasthan.gov.in पर अथवा वरिष्ठ उद्यानविज्ञ के कार्यालय (कमरा नं. NB SF-204) में देखी जा सकती है।

राज.सं.वि.वि.वि./25/8991

वरिष्ठ उद्यानविज्ञ

राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश, निवेशक राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें : मुख्यमंत्री

बिजली-पानी-रोजगार क्षेत्र में हमने लिए हैं अभूतपूर्व निर्णय : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वापरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उधिमयों से आल्हान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनें। शर्मा गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गईं। शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी में देशभर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20 प्रतिशत अकेले राजस्थान से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने विजन डॉक्यूमेंट-2047 को मंजूरी दी है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राजस्थान के सुनहरे



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित किया।

भविष्य का खाका है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 सौर परियोजनाओं को मंजूरी, नई भूमि आवंटन नीति, पंच गौरव जैसे नवाचारों एवं निर्णयों से ऊर्जा एवं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर-पाली औद्योगिक गलियारा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में

50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 जारी की गई है, जो 2030 तक प्रदेश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 125 गीगावाट के स्तर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है तथा 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने

■ “राइजिंग राजस्थान समिट में राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है।”

कहा कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम अभियान’ से प्रेरणा लेते हुए ‘हरियालो राजस्थान’ की शुरुआत की है। अभियान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है तथा अब तक हम 17 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में असीमित अवसरों के साथ प्राकृतिक संसाधन एवं कुशल मानव संसाधन मौजूद हैं।

राज्य सरकार ने पिछले डेढ़ साल में पानी, बिजली, बुनियादी ढांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। साथ ही, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, 1 हजार 300 गांवों को डामर

सड़कों से जोड़ना, मिसिंग लिंक रोड का निर्माण, जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार सहित विभिन्न कार्यों से राज्य में विकास के नए मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रारंभिकता से कार्य किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा तथा ट्रांसमिशन तंत्र को विकसित करने से इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। हमारा संकल्प है कि हम किसान को 2027 तक दिन में बिजली देंगे।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि राजस्थान सरकार सुशासन का पर्याय बन चुकी है। वर्तमान सरकार जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर रही है। यह पहला ऐसा राज्य है, जिसने अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही निवेश समिट का आयोजन किया, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा सतत विकास को बढ़ावा देते हुए हरियालो राजस्थान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसे नवाचार भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार चार गुना शक्ति के साथ राजस्थान को आगे ले जा रही है। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदानी गैस सुरेश पी. मंगलानी, निदेशक एवं सहसंस्थापक एस.ए.ई.एल. इंडस्ट्रीज लि. सुखबीर आवला सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने समिट में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और गणपत्याम मौजूद रहे।

जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम

जयपुर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल और सिम मिलने का रिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर जेल में मोबाइल और सिम मिलने से हड़कंप मच गया। जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले हैं। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। थानाधिकारी बन्नालाल ने जेल अधीक्षक की ओर से मामला दर्ज करवाया है कि 27 अगस्त को जेल प्रशासन की ओर से सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान दो नंबर वार्ड के बैरक नंबर 2 में टॉयलेट के पास एक सिल्वर कलर का छोटा कीपैड मोबाइल और सिम मिली है। इस पर जेल कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी।

करीब 38 हजार रोगियों ने आरजीएचएस योजना के तहत उपचार प्राप्त किया है।

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जिन अस्पतालों ने उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है।

हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध कराएं। निजी अस्पतालों व सभी हितधारकों से चर्चा कर योजना में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। गड़बड़ी पर अंकुश लगाकर योजना का निर्बाध संचालन विभाग की प्राथमिकता है।

‘आर.जी.एच.एस. में 3 5 0 अस्पतालों ने जारी रखीं सेवाएं, 3 8 हजार रोगियों को मिला उपचार’

जयपुर (कासं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। रोगियों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इस दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना में जरूरी बदलाव कर इसे बेहतर बनाया जाए, ताकि लाभार्थियों को सुगमता से उपचार मिले। इसके लिए प्रुफ फुल सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि गुरूवार को भी प्रदेश के

■ **राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल का कहना है कि, “जिन अस्पतालों ने आर.जी.एच.एस. में उपचार बंद कर रखा है, उनके प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद जारी है। हमारा प्रयास है कि सभी अस्पताल योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध करवाएं।”**

ज्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत सुचारू रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर एवं आईपीडी में रोगियों ने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है।

राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ-साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के तहत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं, ताकि जहां भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हों, वहां राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सकें। विगत 4 दिवस में

शाही ठाठ-बाट के साथ जयपुर भ्रमण पर निकले गणेशजी महाराज

मोतीढूंगरी मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मोती ढूंगरी गणेश जी मंदिर से श्री गणेश जन्मोत्सव के अंतर्गत गज पूजन के साथ 38वीं शोभायात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आरती कर शोभायात्रा को रवाना किया। यह पारंपरिक शोभायात्रा गढ़ गणेशजी मंदिर तक निकाली जाती है।

■ **ऑपरेशन सिंदूर एस 400 मिसाइल की तर्ज पर निकाली गई शोभायात्रा रही आकर्षण का केन्द्र**

शोभायात्रा में चित्रस्वरूप भगवान श्री गणेश की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मोती ढूंगरी श्री गणेश मंदिर में दर्शन भी किए। जहां महंत कैलाश शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

शोभायात्रा में आगे ध्वज लिए हाथी को रवाना किया गया। इसके साथ ही शोभायात्रा में 4 हाथी, 11 ऊंट और 21 घोड़े लगाजमे में शामिल हुए । शोभायात्रा की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित थी। इसी के साथ शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियों का संचालन



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती ढूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा को रवाना किया। इस दौरान “ऑपरेशन सिंदूर” थीम पर सजाई गई झांकी आकर्षण का विशेष केन्द्र रही।

किया गया। भव्य शोभायात्रा में राम मंदिर में दर्शन का तांडव नृत्य, रामलला के गणेश, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार, महाकाल, निशान ध्वज लेकर मौजूद रहे। इसके पीछे ऊंट-घोड़े और बैड बाजे के साथ चलते रहे। इस बार शोभायात्रा में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुईं। पारंपरिक हाथी-घोड़े-ऊंट के लगाजमे से लेकर धार्मिक, ऐतिहासिक और समकालीन प्रसंगों को दर्शाती झांकियां सजाई गईं। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और एस-400 मिसाइल की झांकी भी शामिल हुई। झांकियों में भगवान गणेश के विभिन्न

स्वरूपों के साथ-साथ अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन, राम-रावण युद्ध, महाभारत का लेखन, शिव-पार्वती के प्रसंग, माता वैष्णो देवी दरबार, महाकाल, छत्रपति शंभाजी महाराज, केदारनाथ धाम, शेखावाटी की सांस्कृतिक झलक और संत परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। मंदिर समिति के अनुसार, भगवान गणेश की झांकियां स्वचालित तकनीक से भी सजाई गईं।

इनमें गणेशजी का तांडव नृत्य, रिद्धि-सिद्धि संग नृत्य, मृषक पर सवारी, महाकाल रूप, और मोबाइल की लत से दूर रहने का संदेश जैसी झलकियां प्रमुख रहीं। एक झांकी में भगवान शंकर की पीठ पर गणेश जी सवारी करते हुए दिखाए गए।

काशी की प्रसिद्ध मसाने की होली की झांकी भी सजाई गई। गणेश जी के महाभारत लिखने की झांकी सजाई गई। इस झांकी में आदि शिव को भी दिखाया गया है। शोभायात्रा समिति के संयोजक भानु प्रताप ने बताया- इस बार बहुत विशेष झांकियों का आयोजन किया गया है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी और मिसाइल एस 400 भी शामिल है। यह वही मिसाइल है, जिसने पाकिस्तान में जाकर तबाही मचाई। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति को दिखाती हुई झांकी भी शामिल की गई है। इसमें त्रिपालिया गेट से निकलने वाली तीज माता की सवारी की झांकी भी शामिल है।

‘नेता प्रतिपक्ष जूली की सहमति से 2 9 के बजाय 2 8 को रखी सर्वदलीय बैठक, फिर भी कांग्रेस ने किया बहिष्कार’

विधानसभा के मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को बुलाई थी यह सर्वदलीय बैठक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू रूप से चलने के लिए गुरूवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कांग्रेस ने यह कहते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया कि यहां एक तरफा फैसला लिए जाते हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक 2 सितंबर को होगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे।

वहीं दूसरी ओर बैठक के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने कहा कि, विपक्षी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले सभी पक्षों से सहमती ली जाती है। आज की डेट टीकाराम जूली से पूछकर ही तय की गई थी। वे 29 अगस्त को आने में असमर्थ थे, इसलिए जूली के कहने पर 28 अगस्त डेट तय की गई। अचानक उन्होंने सूचना दी कि वे और उनके सचेतक भी नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। गर्ग ने कहा कि जानबूझकर बहिष्कार किया है। इसके कारण अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, डोटसरा वर्सेस जूली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।

गर्ग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है,

■ **सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि, “नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अचानक सूचना दी कि वे और उनके सचेतक बैठक में नहीं आएंगे। ऐसा करना मैदान छोड़ने वाली बात हुई। मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, “डोटसरा वर्सेस जूली” की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।”**

इसकी निंदा करते है। जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विधानसभा को लेकर शुरुआत से ही भाजपा सरकार की मंशा अच्छी नहीं रही है। विधानसभा अध्यक्ष चाह रहे हैं कि सत्र लम्बा चले, लेकिन सरकार चाह रही है कि कुछ दिन में ही विधानसभा सत्र खत्म हो जाए, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित न हो सके। विधानसभा में भी कई वाक्ये ऐसे हुए हैं जो एक पक्षीय रहे। हमारे विधायक नरेन्द्र बुढ़ानिया को विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ दिन में ही हटा दिया गया। इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। जूली ने कहा कि

विधानसभा में सवालों के जवाब पहले जनता के लिए पोर्टल पर अपलोड होते थे, जो इस बार अपलोड नहीं किए गए। क्या सरकार को कोई डर है? जूली ने कहा कि इसी प्रकार जिलों में हमारे प्रधानों, प्रमुखों, चेयरमैनो को चुन-चुनकर हटाया जा रहा है। सरकार के एक विधायक ने जनता के बीच कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सभी

उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

जयपुर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा - 2021 को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। क्योंकि करीब 500 लोग नकल माफिया के साथ सौदा कर परीक्षा में पास हुए। ये लोग पुलिस जैसे सेवेदनशील विभाग में एसआई बनकर जनता के साथ क्या न्याय करते एवं कैसे कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग देते। मैंने पहले दिन से ही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि मेरे पास एसआई पेपर लीक होने के पक्के सबूत थे। मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय एसओजी को ये सभी सबूत दिए। मैंने जैसे ही सबूत दिए वे सही निकलते गये, जिसके लिए आभारन किए, लेकिन पूर्व सरकार की नकल माफिया से सांठगांठ थी।

जवाहर कला केन्द्र में “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” का शुभारंभ

जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केन्द्र स्थित अलंकार आर्ट गैलरी में संयुक्त कला प्रदर्शनी “चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट” का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों - निधि चौधरी, निकिता

■ **चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन**

टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों और कला प्रेमियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी राजस्थान की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है, साथ ही विश्वभर की यात्राओं से मिली प्रेरणाओं को भी दर्शाती है। शगुन अग्रवाल, जो मनोविज्ञान में प्रशिक्षित हैं और बचपन से कला से जुड़ी रही हैं, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से बदलते मानसिक परिदृश्यों



चार प्रतिभाशाली महिला कलाकारों निधि चौधरी, निकिता टाटेर, पारिधि जैन और शगुन अग्रवाल की ओर से जवाहर कला केन्द्र में संयुक्त कला प्रदर्शनी ‘‘चित्रायण: जर्नी थ्रू आर्ट’’ प्रदर्शित की गई है।

को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कला श्रृंखला ए जर्नी इन्वॉड आत्मा-वेषण और आत्मसंवाद की गहरी झलक देती है। शगुन अपने पॉइंटकार्ट ‘शेरदिल्ली’ के जरिये भी व्यक्तिगत और

सामाजिक अनुभवों को जोड़ने का कार्य करती हैं। यह प्रदर्शनी 31 अगस्त 2025 तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी।

वर्तमान में 22 फरवरी 2022 तक की कट ऑफ डेट के अनुसार सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कनेक्शन देय है। राज्य में फिलहाल 78 हजार 498 कृषि कनेक्शन लंबित है, जिनमें डिमाण्ड नोट जमा किए जा चुके हैं।

■ **विकेन्द्रित सौर संयंत्रों से संबद्ध फीडरों में तुरन्त जारी होंगे कृषि कनेक्शन**

मांग पत्र जारी किए जा सकेंगे। मांग पत्र जमा होने के बाद आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन नीति-2017 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्धारित अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) के अनुसार डिमांड नोट जारी किए जाते हैं। मांग पत्र



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की, वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए।

‘सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी

जयपुर, 28 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क, बायपास, आरओबी और आरयूबी जैसी जनउपयोगी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में घंटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने और अकारण देरी पर कॉन्ट्रक्टर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे वसूली की जाएगी। साथ ही, अनियमितता पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त

- मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मानचून में क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।**

कार्यवाही होगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानचून

के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करवाया जाए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेहतर सड़क निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की सूची संधारित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व में बढ़ोतरी के

लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सड़क, बायपास आदि के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण पर उन नीतियों पर विचार करें जिसमें विभाग को भविष्य में राजस्व की बढ़ोतरी हो। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

‘मैंने कभी नहीं कहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सरकार में सब कुछ आरएसएस तय करता है? ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लक्ष्य वही है, जो हमारे देश की भलाई है। उन्होंने सरकार के साथ संघ के समन्वय पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं, बल्कि हर सरकार के साथ हमारा अच्छा समन्वय है...कहीं कोई झगडा नहीं है। आगे जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों का संघ साथ क्यों नहीं देता, तो जवाब में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अच्छे काम के लिए जो हमसे सहायता मांगते हैं हम उन्हें सहायता देते हैं। हम सहायता करने जाते हैं तो जो दूर भागते हैं, उन्हें सहायता नहीं मिलती तो हम क्या करें। आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है जिसको हम सहायता कर रहे

हैं। लेकिन कभी-कभी देश चलाने के लिए या पार्टी का कोई काम चलाने के लिए अगर वो अच्छा है तो हमारे स्वयं सेवक जाकर मदद करते हैं...हमें कोई परहेज नहीं है। सारा समाज हमारा है। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है तो हम उनकी इच्छा का सम्मान करके रूक जाते हैं। आरएसएस ने विभाजन का विरोध नहीं किया, इस सवाल का जवाब देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यह गलत जानकारी है। संघ ने विभाजन का विरोध किया था, लेकिन उस समय संघ के पास क्या ताकत थी। अखंड भारत एक सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के विभाजन को रोकने में संघ की भूमिका को समझना हो तो हो। शेवादि की पुस्तक “ट्रैजिक स्टोरी ऑफ़ पार्टीशन” पढ़ नी चाहिए।

बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय चर्चा है कि जेडीयू 102, भाजपा 101, चिराग पासवान 20, मांझी व उपेन्द्र कुशवाह 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

- कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा तो लाभभग तय हो गया है, पर कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, इस पर चिंतन जारी है।**

गठबंधन की सीट शेयरिंग की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। लेकिन कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी इसका मंथन आगे होगा। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। इस बीच अब सीटों का ये अंलुझा आया है। जेडीयू को अधिक सीटें देकर यह बताते की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

छत्तीसगढ़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
2000 से अधिक लोगों का अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया गया है। शिविरों में रहने, खाने और सोने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।

हाईकोर्ट ने वो कर दिखाया जो ...

- कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य द्वारा जनहित याचिका में 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द करने की गुहार करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता आरती सिंह ने कहा कि परीक्षा में 859 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, और गिरफ्तारियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि अधिकांश अभ्यर्थियों ने अनुचित व गैर कानूनी माध्यमों से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हो सकते हैं, परन्तु वास्तविकता में कितने अभ्यर्थियों ने गलत रास्ते अपनाए थे, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है।**

- अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि आर.पी.एस.सी. द्वारा अपनाई जा रही कुप्रथाओं को देखते हुए हाईकोर्ट इन सभी मामलों पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, जिस पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जाएगी।**

किया। न्यायाधीश समीर जैन ने कहा कि इन अफसरों ने पेपर लोक गिरोह के साथ खुलकर मिलीभगत की और व्यापक स्तर पर पेपर लोक करवाया, जिससे आमजन का आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर से विश्वास उठ सा गया।

अदालत ने अपने आदेश में इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लिया कि एस.ओ.जी. द्वारा की गई जांच में सामने आया था कि परीक्षा (13 से 15 सितम्बर 2021) से एक महिने पहले (अगस्त के पहले हफ्ते में) ही परीक्षा का पेपर लोक हो गया। इस जांच में यह भी सामने आया था कि बाबूलाल कटारा ने सबसे पहले रामूराम रायका को पेपर सौंपा था ताकि वे अपने बच्चों, शोभा और देवेश रायका को द संके। जांच में यह भी सामने आया कि बाबूलाल कटारा ने ही रामूराम रायका को सलाह दी थी कि वे आर.पी.एस.सी. चैयरमेन से मिले ताकि इंटरव्यू में उन्हें अच्छे नम्बर मिल सके। एस.ओ.जी की जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन

आर.पी.एस.सी. चैयरमेन और अधिकारी परीक्षा पेपर लोक करने की साजिश में शामिल थे, और चैयरमेन के साथ-साथ तत्कालीन राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, मंजू शर्मा और बाबूलाल कटारा पेपरों की फोटोकॉपी करने और कैम्परे से फोटो खींचकर पेपर लोक करने की साजिश में शामिल थे। अदालत ने एस.ओ.जी. द्वारा दी गई चार्जशीट और उसमें दिए गए बयानों में आपने आदेश में अंकित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि बाबूलाल कटारा तथा उनके साथ कार्यरत अन्य सदस्य उनके पुत्र और अन्य अभ्यर्थियों के लिए एनपेन चुराने की साजिश में लिप्त थे और अभ्यर्थियों को ‘इंटरव्यू’ के समय पैसे के लेन-देन के बारे में बात करते थे और यह भी तय करते थे कि किस अभ्यर्थी के कितने मार्क्स बढ़ाये जाएँगे।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया कि कई अपराधिक गिरोह, जिनमें कालेर गिरोह और जगदीश विश्नोई गिरोह शामिल हैं, ने 10–10

लाख रुपये में पेपर खरीदे थे। एस.ओ.जी. की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन दोनों गिरोह के बीच में पहले से कोई भी सम्पर्क या समझौता नहीं था, यानि वे केवल गहलोत सरकार के दौरान खुले आम आर.पी.एस.सी. सदस्यों से मिलकर व्यापक पेपर लोक की वारदातों को अंजाम देने के लिए साथ आए थे। अदालत ने यह भी कहा कि एस.आई. भर्ती परीक्षा–2021 की जांच के दौरान 100 से भी अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। अदालत का कहना था कि परीक्षा में 859 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, और गिरफ्तारियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि हर आठ में से एक अभ्यर्थी ने अनुचित व गैर कानूनी माध्यमों से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हो सकते हैं, परन्तु वास्तविकता में कितने अभ्यर्थियों ने गलत रास्ते अपनाए थे, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि 859 पदों में से करीब 800 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में चयनित होने के बाद नियुक्ति ली थी। इन 800

अमेरिकी वीजा की अवधि घटाई जाएगी?

वाशिंगटन, 28 अगस्त। अमेरिकी प्रशासन अपने वीजा नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और अगर ये नियम स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे अमेरिका में रह रहे वीजा धारकों की समस्यावधि घट जाएगी। इससे वहां रह रहे लोगों खासकर छात्रों को अपने देश जल्द वापस लौटना पड़ सकता है।

अमेरिकी गृह विभाग ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित नियम अगर स्वीकार हो जाते हैं तो इससे वीजा के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा और शासन की इन व्यक्तियों की जांच और निगरानी करने को क्षमता बढ़ेगी। यह नियम कुछ ही तरह की वीजा श्रेणी पर लागू होगा और इस श्रेणी में विदेशी छात्रों

- अगर ऐसा हुआ तो वहां काम या पढ़ाई के लिए गए लोगों को जल्दी ही लौटना पड़ सकता है।**

को मिलने वाला वीजा भी शामिल है। अमेरिका के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को लगभग अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है।” विदित हो कि सन 1978 से, यहां आने वाले विदेशी छात्रों को एफ श्रेणी का वीजा एक खास अवधि के लिए दिया जाता रहा है। अन्य वीजा श्रेणी से भिन्न यह वीजा धारकों को बिना किसी अतिरिक्त जांच-पड़ताल के अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने की अनुमति देता है। अब अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि विदेशी छात्रों ने अमेरिकी उदारता का लाभ उठाया है और वे ऐसे “स्थायी” छात्र बन गए हैं, जो अमेरिका में रहने के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में स्थायी रूप से खुद का नामांकन किए रहते हैं।

बिहार में घुसे तीन संदिग्धों पर 5 0 हजार का इनाम घोषित

तीनों पाकिस्तानी संदिग्ध नेपाल की सीमा से बिहार में घुसे हैं राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है

- इस घटनाक्रम के बाद राहुल की वोट अधिकार यात्रा में भी बदलाव किया गया है अब वे खुली जीप की बजाय बंदगाड़ी से यात्रा कर रहें हैं।**

शामिल हैं। पुलिस की ओर से इन तीनों संदिग्धों के नाम, तस्वीर सार्वजनिक कर दिये गये हैं।

पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है।

वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। बिहार में घुसे तीनों आतंकियों का पासपोर्ट भी सामने आया

मोदी जापान और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
देशों के प्रमुख से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर मैं 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम इस यात्रा के दौरान अपनी वैश्विक प्रगतिशील और वैश्विक सझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान देंगे। यह यात्रा हमारे सभ्यतागत बंधनों और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर

होगी जो हमारे लोगों को परस्पर जोड़ते हैं।(पीएम ने कहा कि जापान से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाऊंगा। भारत एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। सात साल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नजदीकी बढा।कर मेक इन इंडिया पहल के लिए समर्थन जुटाएंगे।

‘वैश्विक नेताओं से निजी ...

- इसके लिए भारत पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कभी टैरिफ बढ़ाकर कभी एच वन-बी वीजा के नाम पर तो कभी ऑपरेशन सिंदूर व सीज़फायर पर दावे करके तो कभी रुस -यूक्रेन जंग को मोदी की जंग बताकर।**
- प्र.मंत्री मोदी ने भी इस दबाव को स्वीकार किया और कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, हम उसे सहन करेंगे पर हम किसानों, पशुपालकों व लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेंगे।**

चाहता है कि भारत कृषि बाज़ार को उसके उत्पादों के लिए खोले जो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा भारतीय किसानों की बर्बादी।

एक वरिष्ठ राजनयिक ने जब पूछा गया कि अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ा है, तो उन्होंने कहा: ये सब अर्थव्यवस्था के कारण है।”

वाइट हाउस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी कि “यह केवल रूसी तेल के बारे में नहीं है।”

बेसेंट ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौता वार्ताओं में केवल “दिखावा” किया है।

नवरो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान नेता” बताया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, वह इस सिद्धांत

को मजबूत करता है कि वाशिंगटन की असली चिंता भारत की व्यापारिक बाधाएँ हैं।

नवरो ने कहा कि वे इस बात से हैरान हैं कि “भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहाँ बुद्धिमान लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन वे हमसे आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि ‘हमारे टैरिफ दुनिया में सबसे ऊँचे नहीं हैं’, जबकि सच्चाई यह है कि वे सबसे ऊँचे हैं।”

भारत पर अमेरिकी दबाव का एक और पहलू है – ट्रम्प प्रशासन की एच वन-बी वीजा कार्यक्रम को लेकर नाराजगी, जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारत है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने बुधवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन एच वन-बी कार्यक्रम में बदलाव की योजना बना रहा है, जो

भारत ने ट्रंप की ‘‘टैरिफ ...

- पर, यह भी सच है कि, दीर्घकाल की दृष्टि से, भारत की यह सामना करने की नीति लाभकारी ही रहेगी, पर तत्कालिक रूप से आर्थिक पीड़ा जरूर होगी, क्योंकि भारत के अमेरिका को निर्यात होने वाले 45अरब डॉलर के माल पर भारी संकट आयेगा, कुछ रोजगार भी खत्म हो जायेंगे ।**

गति पर विवाद है, लेकिन यह सुधार अनुपालन को सरल बनाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है। यह भारत के सुधार एजेंडे की निरंतरता को भी दर्शाता है, जिससे निवेशकों को यह परेशान मिलता है कि बाहरी उथल-पुथल से आंतरिक नीतिगत प्रगति बाधित नहीं होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गोबा के नेतृत्व में दो उच्चस्तरीय समितियाँ नियामक छूट और संरचनात्मक सुधारों के खके तैयार कर रही हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री

सलाह देती है यानि प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद। यह दिखाता है कि भारत बाहरी झटकों के जवाब में दीर्घकालिक योजना और त्वरित आर्थिक सलाह दोनों को सक्रिय रूप से जुटा रहा है।

अल्पकाल में, टैरिफ वृद्धि से नुकसान होगा। श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यातकों को दबाव का सामना करना पड़ेगा, और वैकल्पिक बाजार विकसित होने से पहले व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। फिर भी, मोदी सरकार इस अस्थिरता को एक उल्टेपक्ष के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। घरेलू खपत पर दंव लगाकर, सुधारों में तेजी लाकर और वैश्विक सझेदारियों में विविधता लाकर, नई दिल्ली टैरिफ झटके को दीर्घकालिक लाभ में बदलने की रणनीति अपना रही है। हालाँकि इसका लाभ असमान रूप से मिलेगा। अल्पकालिक दर्द टालना संभव नहीं है। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका लाभ एक अधिक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकती है – जो वाशिंगटन को व्यापार नीति की अनिश्चितताओं से कम प्रभावित हो, और अपनी घरेलू मांग व विविध वैश्विक संबंधों पर अधिक आधारित हो।